



Yojna IAS

C-32 NOIDA SECTOR-02  
UTTAR PRADESH (201301)  
CONTACT No. +8595907569

## CURRENT AFFAIRS



**Date - 4 Feb 2022**

### पांच नदी-जोड़ने की परियोजना: केंद्रीय बजट

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारत में 'पांच नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं' का प्रस्ताव रखा है।

#### परियोजना के लिए पहचानी गई नदियां:

- गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार और पेन्नार-कावेरी, दमनगंगा-पिंजाल और पर-तापी-नर्मदा।

#### इन नदियों का संक्षिप्त विवरण:

- कृष्णा नदी भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- कावेरी नदी 'कोडागु' से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है।
- पेन्नार नदी 'चिक्कबल्लापुरा' से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है।
- गोदावरी नदी भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह नासिक से निकलती है और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है।
- दमनगंगा-पिंजाल नदी जोड़ने की परियोजना का उद्देश्य मुंबई शहर के लिए घरेलू पानी उपलब्ध कराने के लिए दमनगंगा बेसिन से अधिशेष पानी को शहर की ओर मोड़ना है।
- 'पर-तापी-नर्मदा परियोजना' के तहत, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित सात जलाशयों से अतिरिक्त पानी को कच्छ और सौराष्ट्र के संदिग्ध क्षेत्रों में मोड़ने का प्रस्ताव है।

#### इंटरलिंगिंग के लाभ:

- जल और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि
- पानी का उचित उपयोग
- कृषि को बढ़ावा
- आपदा न्यूनीकरण

- परिवहन को बढ़ावा

### संबंधित विवाद और चिंताएं:

- नदियों को आपस में जोड़ना बहुत महंगा प्रस्ताव है। इससे लाखों लोगों की भूमि, जंगल, जैव विविधता, नदियों और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- नदियों को आपस में जोड़ने से जंगलों, आर्द्रभूमियों और स्थानीय जल निकायों का विनाश होगा। आर्द्रभूमि भूजल पुनर्भरण का एक प्रमुख तंत्र है।
- ऐसी परियोजनाओं से लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। यह विस्थापितों के पुनर्वास के मुद्दे से निपटने के लिए सरकार पर भारी बोझ डालता है।
- नदियों को आपस में जोड़ने से समुद्र में गिरने वाले ताजे पानी की मात्रा कम होगी और समुद्री जीवन को गंभीर खतरा होगा।

## ‘हर घर, नल से जल’ योजना

- ‘हर घर, नल से जल’ योजना के तहत वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में 8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

### ‘हर घर, नल से जल’ योजना:

- योजना का शुभारंभ: वर्ष 2019 में।
- नोडल एजेंसी: जल शक्ति मंत्रालय
- उद्देश्य: 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पाइप से पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- यह सरकार ‘जल जीवन मिशन’ के प्रमुख कार्यक्रम का एक घटक है।

### कार्यान्वयन:

- योजना एक अद्वितीय मॉडल पर आधारित है। इसमें ग्रामीणों को शामिल करते हुए ‘जल समितियां’ बनाई जाती हैं, और ये समितियां तय करती हैं कि गांव वाले अपने द्वारा उपभोग किए जाने वाले पानी के लिए क्या भुगतान करेंगे।
- जल समितियों द्वारा निर्धारित शुल्क गांव के सभी निवासियों के लिए एक समान नहीं होगा। जिन ग्रामीणों के घर बड़े होंगे, उन्हें अधिक भुगतान करना होगा, जबकि गरीब परिवार या बिना कमाने वाले सदस्य वाले परिवारों को इस शुल्क से छूट दी जाएगी।

### मांग:

- 2018 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 600 मिलियन भारतीयों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ता है, और सुरक्षित पानी तक अपर्याप्त पहुंच के कारण हर साल लगभग दो लाख लोगों की मौत हो जाती है।

- 2030 तक, देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति को दोगुना करने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि लाखों लोगों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ेगा और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 6% की कमी आएगी।
- अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि 84% ग्रामीण परिवारों के पास पाइप से पानी नहीं है और देश का 70% से अधिक पानी दूषित है।

### ‘जल जीवन मिशन’:

- ‘जल जीवन मिशन’ के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक हाउस टैप कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है।
- यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इसे 2019 में लॉन्च किया गया था।

### कार्यान्वयन:

- ‘जल जीवन मिशन’ पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा और संवाद शामिल हैं।
- इस मिशन का मकसद पानी के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना है, जिसके जरिए यह सबकी प्राथमिकता बने।
- इस मिशन के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10; अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में; और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

## ब्रह्मोस का निर्यात: फिलीपींस

- हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मिसाइल के लिए यह पहला निर्यात ऑर्डर है, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है।
- दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच फिलीपींस इस मिसाइल को शामिल करना चाहता है।
- कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ चर्चा उन्नत चरणों में है।

### ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं:

- ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और रूस के एनपीओएम के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।

- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे जमीन, हवा और समुद्र और बहु-क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो दिन-रात किसी भी मौसम में काम करती है।
- यह 'आग और भूल जाओ' के सिद्धांत पर काम करता है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
- ब्रह्मोस सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मच 8 की गति से संचालित होती है, जो ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना है।
- हाल ही में ब्रह्मोस (विस्तारित श्रेणी सी-टू-सी संस्करण) के एक उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया था।
- जून 2016 में भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) में शामिल होने के बाद, अगले चरण में इसकी सीमा बढ़ाकर 450 किमी कर दी गई और 600 किमी तक विस्तार करने की योजना है।
- ब्रह्मोस मिसाइल को शुरू में 290 किमी की दूरी पर दागा गया था।

### मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर):

- यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक और स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300 से अधिक की दूरी तक ले जाने में सक्षम है।
- उन सदस्यों को गैर-सदस्यों के एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से प्रतिबंधित किया गया है।
- ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिए जाते हैं।
- यह सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और मिसाइल प्रणालियों के लिए निर्यात नीतियों और इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने के लिए नियम-आधारित विनियमन तंत्र के साथ सदस्य राज्यों का एक गैर-संधि संघ है। कुछ दिशानिर्देश हैं।
- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में जी-7 देशों- यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान द्वारा की गई थी।

### भारत के रक्षा निर्यात की स्थिति:

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार के अभियान का रक्षा निर्यात एक स्तंभ है।
- 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरीशस, इज़राइल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, चिली और स्पेन आदि जैसे देशों को हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति की है।
- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम और रडार सिस्टम शामिल हैं।
- हालांकि, भारत का रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुंचा है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2015-2019 के लिए प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वां स्थान दिया है।
- भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 17% निर्यात करता है।
- रक्षा निर्यात में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अभी तक निर्यात के लिए कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।
- निर्यात का विषय अलग-अलग निगमों पर छोड़ दिया जाता है, जैसे 'ब्रह्मोस' या 'डिफेंस पब्लिक शिपयार्ड' और अन्य उपक्रम।
- इस संदर्भ में, 'डिफेंस एक्सपोर्ट्स: अनटैप्ड पोटेंशियल' शीर्षक वाली केपीएमजी रिपोर्ट में एक विशेष "डिफेंस एक्सपोर्ट हेल्प डेस्क" की स्थापना के पहले चरण की सिफारिश की गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्प-डेस्क से प्राप्त इनपुट के आधार पर भारतीय कंपनियां निर्यात के लिए सरकारी मशीनरी के साथ काम कर सकती हैं।
- यदि भारत पड़ोसी देशों को एक बड़ी सैन्य प्रणाली प्रदान करने में सफल हो जाता है, तो यह न केवल रक्षा निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक कदम भी होगा, जैसा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार में है। एशिया के कई देशों को रक्षा उत्पाद उपलब्ध कराता है।
- 

## शीतकालीन ओलंपिक

- शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन के लिए रूसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और मध्य एशिया के पांच राष्ट्रपति चीन पहुंचेंगे।

### यात्रा का महत्व:

- रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन के साथ चल रहे संकट पर चीनी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे।
- चीन के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन रूस-यूक्रेन संकट पर काफी हद तक चुप है।
- चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) योजना में तेजी आने की उम्मीद है क्योंकि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री चीन के साथ निवेश पर चर्चा कर रहे हैं।
- चीन ने यह भी घोषणा की है कि वह पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रहों के विकास पर चर्चा करना चाहता है और पाकिस्तान अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण में सहयोग करना चाहता है।
- अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने कथित मानवाधिकार उल्लंघन के कारण चीन के शिनजियांग प्रांत में खेलों के "राजनयिक बहिष्कार" की घोषणा की है।

### शीतकालीन ओलंपिक:

- शीतकालीन ओलंपिक उन खेलों का मुख्य आयोजन है जो बर्फ पर खेले जाते हैं।
- यह हर चार साल में आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के प्रतिभागी भाग लेते हैं।
- आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, स्कीइंग और फिगर स्केटिंग शीतकालीन खेलों में खेले जाने वाले कुछ लोकप्रिय खेल हैं।
- पहला शीतकालीन ओलंपिक वर्ष 1924 में फ्रांस के शैमॉनिक्स में आयोजित किया गया था।

- शीतकालीन खेलों को शुरू में केवल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान ही खेला गया था, 1908 के लंदन ओलंपिक ने चार स्केटिंग स्पर्धाओं की मेजबानी की थी, और एंटवर्प में 1920 के ओलंपिक में स्केटिंग के साथ-साथ आइस हॉकी भी शामिल थी।
- हालांकि, वर्ष 1924 में, शीतकालीन खेलों के लिए एक अलग कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे 'अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह' कहा जाता है।
- यह 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मेजबान देश शैमॉनिक्स, फ्रांस में आयोजित किया गया था।
- दो साल बाद, शैमॉनिक्स में 'अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल सप्ताह' को आधिकारिक तौर पर पहले शीतकालीन ओलंपिक खेलों के रूप में मान्यता दी गई थी।
- इस साल के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 फरवरी से 20 फरवरी, 2022 तक बीजिंग, चीन में होगा।
- भारत 1964 से शीतकालीन ओलंपिक में भाग ले रहा है।

**Swadeep Kumar**

Yojna IAS